शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh
A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly International E-Journal
ISSN-2993-4648 Year/Volume: 04, Issue: 14 | April - June 2026 | Impact Factor: 4.5 Page – 50 – 53

इंदौर शहर में स्वच्छ भारत मिशन का आर्थिक महत्व: एक मात्रात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजय मुवेल
पीएचडी शोधार्थी
अर्थशास्त्र विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर म.प्र.
ORCID: 0009-0002-9329-4361 ईमेल: Vjmuwel123@gmail.com Mob-8959159850

प्रो. रजनी भारती
पीएचडी मार्गदर्शक
प्रोफेसर (अर्थशास्त्र, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर (म.प्र.)
(ORCID: 0009-0001-4609-540X) ईमेल: rajnibharti66@gmail.com

Received– 25 June - 2026
Accepted-26 June- 2026
Published– 30 June 2026
Corresponding Author-
विजय मुवेल
पीएचडी शोधार्थी
अर्थशास्त्र विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर म.प्र. ORCID: 0009-0002-9329-4361 ईमेल: Vjmuwel123@gmail.com Mob-8959159850
DOI-https://doi.org/10.67275/SU.2026.041412
Funding Policy-
'Shodh Utkarsh' is an independent journal and receives no financial support or grant from any public, commercial, or not-for-profit organization.
वित्त पोषण नीति-
'शोध उत्कर्ष' एक स्वतंत्र पत्रिका है। इसे किसी भी सार्वजनिक, वाणिज्यिक या गैर-लाभकारी संगठन से कोई वित्तीय सहायता, अनुदान या फंडिंग प्राप्त नहीं होती है।
Copyright Notice -
© 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
कॉपीराइट सूचना-
© २०२६ लेखक। यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स अ Attribution 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस (CC-BY 4.0) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है।

सारांश (Abstract):स्वच्छ भारत मिशन (SBM) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक पहल है,जिसका उद्देश्य स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था में सुधार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस मिशन के अंतर्गत इंदौर शहर ने राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रथम स्थान प्राप्त कर एक प्रभावी एवं आदर्श शहरी मॉडल प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में इंदौर शहर में स्वच्छ भारत मिशन के आर्थिक महत्व का वर्णनात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन वर्ष 2014 से 2023 तक की अवधि के द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोध में स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न आर्थिक आयामों जैसे रोजगार सृजन,स्वास्थ्य व्यय में कमी नगर निगम राजस्व, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से प्राप्त आय तथा पर्यटन एवं निवेश में वृद्धि का अध्ययन किया गया है।

द्वितीयक आंकड़ों, तुलनात्मक विश्लेषण तथा लागत–लाभ दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने इंदौर की शहरी अर्थव्यवस्था को सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छता सुधारों ने न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है,बल्कि रोजगार के अवसरों,आर्थिक गतिविधियों और शहर की निवेश क्षमता को भी बढ़ावा दिया है।

मुख्य शब्द-: स्वच्छ भारत मिशन, इंदौर,शहरी अर्थव्यवस्था , रोजगार ,स्वास्थ्य व्यय ,आर्थिक विकास।

1. प्रस्तावना:-स्वच्छता को लंबे समय तक केवल सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय माना जाता रहा है, किंतु आधुनिक आर्थिक अध्ययन यह सिद्ध करते हैं कि स्वच्छता और आर्थिक विकास के मध्य घनिष्ठ संबंध है। अस्वच्छ वातावरण के कारण रोगों में वृद्धि होती है, जिससे श्रम उत्पादकता घटती है और सरकार व परिवारों पर स्वास्थ्य व्यय का बोझ बढ़ता है।

भारत जैसे विकासशील देश में तीव्र शहरीकरण के कारण नगरों में ठोस अपशिष्ट, जल-प्रदूषण और सार्वजनिक स्वच्छता गंभीर समस्याएँ बन गई हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। मध्यप्रदेश का इंदौर शहर इस मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह अध्ययन इंदौर शहर में SBM के आर्थिक प्रभावों का विस्तृत और संख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh
A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly International E-Journal
ISSN-2993-4648 Year/Volume: 04, Issue: 14 | April - June 2026 | Impact Factor: 4.5 Page – 50 – 53

2. साहित्य समीक्षा:-विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि स्वच्छता निवेश का प्रतिफल (Return on Investment) अत्यधिक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता पर किया गया प्रत्येक 1 रुपये का निवेश औसतन 4 से 5 रुपये का आर्थिक लाभ देता है। भारत में शहरी स्वच्छता पर केंद्रित अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि स्वच्छ शहरों में स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर होते हैं तथा निवेश और पर्यटन में वृद्धि होती है। हालांकि, इंदौर शहर पर केंद्रित संख्यात्मक आर्थिक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं, जिसे यह शोध पूरा करता है।

स्वच्छता के प्रारंभिक प्रयास और विकास:इतिहास की समीक्षा से पता चलता है कि भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जिसके बाद 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। 2014 में ये सभी प्रयास स्वच्छ भारत मिशन के रूप में पुनर्गठित किये गए, जिसमें 'ओपन डिफेकेशन फ्री' (ODF) भारत का लक्ष्य रखा गया। इस मिशन को 2019 में राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई थी, और बाद में मिशन को 2.0 के रूप में अधिक व्यापक और टिकाऊ स्वरूप दिया गया।

स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर शोध:-विश्व स्तर पर शोध यह संकेत देता है कि स्वच्छता में सुधार केवल स्वास्थ्य लाभ दिए बिना नहीं है, बल्कि आर्थिक लाभ भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, स्वच्छता के विस्तार से घरेलू खर्च में कमी आती है और उत्पादकता बढ़ती है। एक नवीनतम आर्थिक विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 2014–19 में स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल खुले में शौच की प्रथा को कम किया बल्कि स्वास्थ्य-संबंधी रोगों में कमी लाई, जिससे घरेलू और सामाजिक स्वास्थ्य व्यय में कमी देखी गई।

इसके अतिरिक्त, अन्य शोधों में यह भी पाया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का पूरे देश में व्यापक आर्थिक लाभ लगभग 4.3 ट्रिलियन रुपये (लगभग USD 76 बिलियन) तक पहुंचा है, और खर्च पर सामाजिक लाभ 4.3 गुना तक माना जाता है। यानी स्वच्छता में निवेश ने दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान किए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के आर्थिक फायदों का तुलनात्मक मूल्यांकन:-स्वच्छ भारत मिशन के आर्थिक लाभ को मापने वाले शोध अध्ययनों से पता चलता है कि स्वच्छता में निवेश से हर घर को ₹53,536 प्रति वर्ष लाभ हुआ है, और दस वर्षों के दौरान खर्च का लाभ लगभग 4.3 गुना रहा है। इसका अर्थ है कि स्वच्छता में की गई सरकारी व निजी दोनों तरह की खर्च "लागत-लाभ" दृष्टिकोण से अत्यधिक सकारात्मक परिणाम देती है।

नगरीय और ग्रामीण स्वच्छता में तुलनात्मक अध्ययन:-अन्य शोधों ने स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण और नगरीय प्रभावों की तुलना की है। नगरों में, स्वच्छ भारत मिशन के परिणामस्वरूप बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण और नागरिक सेवा प्रणालियों में नवीनीकरण देखा गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह मिशन मुख्यतः खुले में शौच से मुक्ति, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर करने में प्रभावी रहा है।

नीतिगत और व्यवहारिक चुनौतियां:-कुछ साहित्य में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में नीति और व्यवहार से जुड़े प्रतिबंधों की भी चर्चा है। शोधों में यह पाया गया है कि तकनीकी अवसंरचना, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी, स्वच्छ भारत मिशन के दीर्घकालिक प्रभावों को सीमित कर सकती है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन ने कई शहरों में सफलता पाई है, कमजोर स्थानीय प्रशासन और *कचरा प्रबंधन प्रणालियों की अपर्याप्तता* जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

3. अध्ययन के उद्देश्य:

- इंदौर शहर में स्वच्छ भारत मिशन के आर्थिक प्रभावों का संख्यात्मक विश्लेषण करना।
- स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का मूल्यांकन करना।
- स्वास्थ्य व्यय में आई कमी का आर्थिक आकलन करना।
- नगर निगम के राजस्व पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव का अध्ययन करना।

पर्यटन एवं निवेश पर स्वच्छता के प्रभाव का विश्लेषण करना।

4. अनुसंधान पद्धति:-प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। आँकड़ों के प्रमुख स्रोतों में इंदौर नगर निगम की वार्षिक रिपोर्टें, स्वच्छ भारत मिशन के सरकारी दस्तावेज, शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्टें एवं शोध पत्र शामिल हैं। विश्लेषण हेतु तुलनात्मक विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा लागत-लाभ विश्लेषण (Cost–Benefit Analysis) पद्धति का प्रयोग किया गया है।

5. इंदौर शहर में स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन:-इंदौर नगर निगम द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण,कंपोस्टिंग, बायो-सीएनजी संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय, ODF++, Water+ मानक तथा व्यवहार परिवर्तन

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh
A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly International E-Journal
ISSN-2993-4648 Year/Volume: 04, Issue: 14 | April - June 2026 | Impact Factor: 4.5 Page – 50 – 53

अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप इंदौर वर्ष 2017 से निरंतर भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है।

6. स्वच्छ भारत मिशन का आर्थिक महत्त्व : संख्यात्मक विश्लेषण:

6.1 रोजगार सृजन - स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए।

तालिका 1 : SBM के अंतर्गत रोजगार सृजन (अनुमानित)

वर्ष	प्रत्यक्ष रोजगार	अप्रत्यक्ष रोजगार	कुल रोजगार
2015	3,200	1,500	4,700
2018	5,800	3,200	9,000
2022	7,500	5,000	12,500

तालिका से स्पष्ट है कि स्वच्छता गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार में निरंतर वृद्धि हुई है।

6.2 स्वास्थ्य व्यय में कमी और उत्पादकता में वृद्धि-स्वच्छ वातावरण के कारण जलजनित रोगों में कमी आई, जिससे परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में गिरावट हुई।

तालिका 2 : स्वास्थ्य व्यय में कमी (अनुमानित)

वर्ष	प्रति परिवार औसत स्वास्थ्य व्यय (₹)
2014	6,500
2018	4,800
2022	3,900

इससे श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई और कार्य-दिवसों की हानि में कमी आई।

6.3 नगर निगम के राजस्व पर प्रभाव -कचरे से खाद एवं बायो-सीएनजी उत्पादन ने नगर निगम के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न की।

तालिका 3 : इंदौर नगर निगम का SBM से संबंधित राजस्व (₹ करोड़ में)

वर्ष	खाद एवं ऊर्जा	अन्य शुल्क	कुल राजस्व
2016	12	18	30
2019	28	32	60
2022	45	40	85

6.4 पर्यटन एवं निवेश पर प्रभाव-स्वच्छता रैंकिंग के बाद इंदौर में पर्यटन एवं निवेश में वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 4 : पर्यटन आगमन (लाख में)

वर्ष	पर्यटकों की संख्या
2014	18
2018	27
2022	38

6.5 लागत-लाभ विश्लेषण (Cost–Benefit Analysis)

स्वच्छ भारत मिशन पर किए गए व्यय की तुलना में प्राप्त आर्थिक लाभ अधिक पाए गए।

मद	राशि
कुल निवेश	650
प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ	1,450
अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ	1,200
कुल लाभ	2,650

7. प्रमुख निष्कर्ष:

- स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंदौर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई।
- स्वास्थ्य व्यय में कमी से परिवारों की वास्तविक आय बढ़ी।
- नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई।
- पर्यटन एवं निवेश में निरंतर वृद्धि हुई।
- स्वच्छ भारत मिशन का लाभ-लागत अनुपात सकारात्मक पाया गया।

8. निष्कर्ष:-यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि स्वच्छ भारत मिशन इंदौर शहर के लिए केवल स्वच्छता कार्यक्रम नहीं बल्कि एक प्रभावी आर्थिक विकास रणनीति सिद्ध हुआ है। स्वच्छता निवेश ने रोजगार, स्वास्थ्य, राजस्व और शहरी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया है। इंदौर मॉडल को अन्य भारतीय नगरों में अपनाकर सतत एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

9. सुझाव:

- शहरी स्वच्छता अवसंरचना की नियमित निगरानी (Monitoring) सुनिश्चित की जाए, विशेषकर जल आपूर्ति लाइनों, सीवर नेटवर्क एवं अपशिष्ट भंडारण स्थलों की, ताकि इंदौर (भागीरतपूरा) दूषित जल से भयंकर जन हानी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
- चूहा नियंत्रण (Rodent Control) हेतु वैज्ञानिक एवं सतत कार्यक्रम लागू किए जाएँ, जिसमें ठोस अपशिष्ट स्थलों, नालियों, खाद्य भंडारण क्षेत्रों एवं जल टंकियों का नियमित

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh
A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly International E-Journal
ISSN-2993-4648 Year/Volume: 04, Issue: 14 | April - June 2026 | Impact Factor: 4.5 Page – 50 – 53

- कीट-नियंत्रण शामिल हो। ताकि महाराजा यशवंत राव शासकीय अस्पताल इंदौर की हर्दय विदारक घटना चूहा कांड जैसी घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो।
- पेयजल आपूर्ति प्रणाली में Water Safety Plan (WSP) को अनिवार्य किया जाए, जिससे दूषित जल की समस्या को स्रोत स्तर पर ही रोका जा सके।
- जल गुणवत्ता की रियल-टाइम जांच प्रणाली (जैसे सेंसर आधारित मॉनिटरिंग) को अपनाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की संदूषण की सूचना समय रहते मिल सके।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 'स्वास्थ्य–स्वच्छता–जल' (Health–Sanitation–Water Nexus) को नीति स्तर पर जोड़ा जाए, जिससे स्वच्छता की उपलब्धियाँ स्वास्थ्य संकट में परिवर्तित न हों।
- नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग एवं जल आपूर्ति एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए, ताकि आकस्मिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई संभव हो।
- नागरिक सहभागिता एवं जागरूकता अभियानों को और सशक्त किया जाए, जिससे नागरिक दूषित जल, कचरा जमाव या अस्वच्छ परिस्थितियों की तुरंत सूचना प्रशासन को दे सकें।
- स्वच्छता आधारित MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हुए, कीट-नियंत्रण, जल शुद्धिकरण और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी नवाचार तकनीकों को अपनाया जाए।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र (Emergency Response Mechanism) विकसित किया जाए, ताकि किसी भी स्वच्छता या जल-स्वास्थ्य संकट की स्थिति में जन-स्वास्थ्य एवं आर्थिक नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

****

10. संदर्भ:

1.Indore Municipal Corporation. (2016). *Annual administrative report*. Indore: IMC.
2.Indore Municipal Corporation. (2017). *Swachh Bharat Mission (Urban): City level implementation report*. Indore: IMC.
3.Indore Municipal Corporation. (2018). *Solid waste management system in Indore city*. Indore: IMC.
4.Indore Municipal Corporation. (2019). *Financial performance and revenue generation under SBM*. Indore: IMC.
5.Indore Municipal Corporation. (2020). *Urban sanitation, public health and economic outcomes: Indore experience*. Indore: IMC.
6.Indore Municipal Corporation. (2021). *Annual budget and municipal revenue report*. Indore: IMC.
7.Indore Municipal Corporation. (2021). *Bio-CNG plant and waste-to-energy project report*. Indore: IMC.
8.Indore Municipal Corporation. (2022). *Swachh Survekshan preparedness and performance report*. Indore: IMC.
9.Indore Municipal Corporation. (2022). *Health expenditure savings due to improved sanitation in Indore*. Indore: IMC.
10.Indore Municipal Corporation. (2023). *Economic impacts of Swachh Bharat Mission in Indore city*. Indore: IMC.
11.Ministry of Housing and Urban Affairs. (2015). *Swachh Bharat Mission (Urban): Operational guidelines*. Government of India.
12.Ministry of Housing and Urban Affairs. (2022). *Swachh Bharat Mission–Urban 2.0: Implementation framework*. Government of India.
13.World Health Organization. (2012). *Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions*. Geneva: WHO.
14.World Health Organization. (2018). *Sanitation and economic development*. Geneva: WHO.
15.UNICEF. (2018). *Economic impacts of sanitation in India*. New Delhi: UNICEF India.
16.World Bank. (2019). *Economic impacts of inadequate sanitation in urban India*. Washington, DC: World Bank.
17.Kumar, A. (2018). Swachh Bharat Mission: A missed opportunity for the Indian economy. *Arthshastra: Indian Journal of Economics & Research*, 7(3), 40–52.
18.World Development. (2020). Comparison of the costs and benefits of the Clean India Mission. *World Development*, 134, 105052.
19.Asian Development Bank. (2016). *Urban sanitation and economic productivity in Asia*. Manila: ADB.
Ministry of Health and Family Welfare. (2018). *National health profile*. Government of India.